पं॰ अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की अर्थनीति

डॉ. संगीता कुमारी

पं॰ अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्ववाली राजग सरकार द्वारा जब सत्ता संभाली गयी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदारीकरण का दौड़ आरंभ हो चुका था। नरसिन्हा राव की सरकार ने उदारीकरण एवं आर्थिक ढाँचा को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठा चुके थे।

1980 में जब भाजपा का गठन हुआ, तो पं॰ अटल बिहारी वाजपेयी ने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में महात्मा गाँधी के न्यासिता के सिद्धांत को स्वीकार किया और कहा, समाजवाद और पूँजीवाद दोनों एक ही प्रकार की विषमता, अमानवीयता, हिंसा, स्वार्थ, लोभ, अनियंत्रित उपभोक्तावाद तथा अन्यताभाव (एलीनेशन) जैसी बुराइयों को जन्म देती है। गाँधी का न्यासिता का सिद्धांत संसार को तीसरा रास्ता दिखा सकता है।

पं॰ अटलजी ने स्वदेशी को स्पष्ट करते हुए कहा, स्वदेशी का अर्थ यह नहीं होता कि भारत आर्थिक क्षेत्र में विश्व से अलग खड़ा रहेगा। स्वदेशी का मतलब उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक उपयोग और कड़े श्रम से आधुनिक और समृद्ध भारत बनाने का विश्वास जगाना है।

विदेशी पूँजी निवेश की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए कहा, सरकार नई औद्योगिक नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। इस दिशा में पब्लिक सेक्टर में निजी पूँजी निवेश को आमंत्रित करने से पहले सरकार को पहल कर विपक्ष को विश्वास में लेने का आग्रह किया और कहा, वैसी सरकारी उद्यम, जो घाटे में चल रही है, उनका निजीककरण किया जाय और विदेशी पूँजी का उपयोग मूल उद्योग की स्थापना में लगाया जाय।

निजीकरण का मतलब सार्वजनिक इकाइयों के शेयरों को निजी क्षेत्र में बेचकर उसकी भागीदारी बढ़ाना होता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र की सहभागिता

को बढ़ाकर सार्वजनिक उपक्रमों की कमिया एवं विफलताओं पर सकारात्मक नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पं॰ अटलजी की निजी आर्थिक मान्यता और उन पर गाँधी के न्यासिता सिद्धांत या पं॰ दीनदयालजी के एकात्म मानववाद का सिद्धांत का चाहे, जो भी प्रभाव रहा हो, राजनीतिक यथार्थताओं से वे अपने को पृथक नहीं कर पाये। उन्हें अपनी सिद्धांतों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में समायोजित होने के लिए

बाध्य होना पड़ा।